पेज 02
झीरम की पूरी साजिश की जांच के लिए अड़ गई कांग्रेस



साप्ताहिक
# शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 21 सितंबर से 27 सितंबर 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08
टीएस सिंहदेव का बयान और 52 करोड़ की घटती संपत्ति



वर्ष : 02 अंक : 29 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com



पेज 04 खुरचन : विकास दौड़ रहा है, रायपुर जाम में खड़ा है


# छात्र नीति ABVP 'JEN-Z' NSUI रणनीति

## 37 करोड़ युवाओं के वोट बैंक के लिए मचेगा घमासान

**दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट-सेक्रेटरी पद ABVP को**

**17 साल बाद कोई निर्दलीय उपाध्यक्ष पद पर जीता है**

**जब NSUI हार रही थी तब राहुल 'छात्रों की गूंज' में थे**

**देश की छात्र शक्ति को साधने में जुटी सियासी पार्टियां**

**मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी**
**मोबाईल नंबर 7000681023**


सवाल उठने लगा है JEN Z के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली सियासी जमात कौन है? देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक दलों में आने वाले वक्त में 37 करोड़ युवाओं के वोट बैंक के लिए घमासान मचा हुआ है। देश का युवा भी कन्फ्यूज है क्योंकि एक परंपरा और संस्कार से बंधा है तो दूसरा सिस्टम से बेतहाशा नाराज। दिल्ली की सड़कों में JEN Z की ताकत, प्रदर्शन और इसको लीड करने वाले हाई प्रोफाइल यूथ की प्लानिंग भाजपा-कांग्रेस दोनों ही समझ चुके हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत बड़ा और प्रभावशाली वर्ग है जिसे साधने के लिए दोनों ही दल बेताब हैं। ऐसे में युवाओं के दो विचार भरे परिणाम और हालत दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव ABVP की फ़तह से तो इंदौर में हुए राहुल गांधी की शिरकत 'छात्रों की गूंज' से देश के युवा कुछ कुछ समझने लगे हैं।

**शहर सत्ता/ दिल्ली//इंदौर/रायपुर।** दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन पदों पर जीत हासिल की। ABVP के यश डबास अध्यक्ष बने हैं। वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता। उन्हें 30 हजार से ज्यादा वोट मिले। पिछले 17 सालों में यह पहली बार है जब DUSU के केंद्रीय पैनल में कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता हो। इससे पहले 2009 में निर्दलीय मनोज चौधरी और 1991 में निर्दलीय राजीव गोस्वामी DUSU अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI को एक भी पद हासिल नहीं हुआ। DUSU चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और 1,51,519 छात्रों में से 61,312 ने मतदान किया।

### दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस, इनमें 91 कॉलेज, चुनाव 52 में

दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो कैंपस हैं। साउथ और नॉर्थ कैंपस लगभग 15 किमी की दूरी पर बने हैं। दोनों कैंपस मिलाकर DU में 91 कॉलेज आते हैं, लेकिन DUSU के चुनावों में DU के सभी कॉलेज वोट नहीं कर सकते हैं। DUSU में सिर्फ 52 कॉलेज और फैकल्टी ही सीधे तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। सेंट स्टीफंस, लेडी श्री राम और जीसस एंड मैरी जैसे कुछ बड़े कॉलेज भी DUSU का हिस्सा नहीं हैं।

### 'छात्रों की गूंज' में राहुल के बोल-

सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसलिए अंधभक्त तैयार करता है। राहुल ने स्टूडेंट और अंधभक्त के बीच 4 अंतर गिनाए...पहला, जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है। दूसरा जहां स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है अंधभक्त नफरत फैलाता हे। तीसरा, जहां स्टूडेंट निडर होता हे वहां अंधभक्त डरपोक होता है। चौथा, जहां स्टूडेंट महिलाओं की इज्जत करता हे अंधभक्त महिलाओं का अपमान करता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे इसलिए सिस्टम अंधभक्तत को तैयार करता है, उन्हें प्रमोट करता है।

### कांग्रेस की नजर 37 करोड़ युवाओं वोटर्स पर

अभी जो युवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं या UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NEET-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे आने वाले वर्षों के अहम वोटर्स हैं। भारत में 15-29 वर्ष की उम्र के करीब 36.7 करोड़ युवा हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत बड़ा और प्रभावशाली वर्ग है। कांग्रेस इसी वर्ग की समस्याओं- पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती में देरी, महंगी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था- को 'छात्रों की गूंज' जैसे कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक मुद्दा बना रही है।

***अमित शाह बोले***

*दिल्ली विश्वविद्यालय केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ देश के हर कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यहाँ का जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब होता है। आज @ABVPVoice को मिली शानदार जीत उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो युवा शक्ति को राष्ट्रविरोधी एजेंडे की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। देश का युवा आज राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है और यही इस जनादेश का सबसे बड़ा संदेश है।*

***नितिन नबीन बोले***

*दिल्ली यूनिवर्सिटी में DUSU चुनावों में ABVP की ऐतिहासिक जीत पर मेरे सभी युवा दोस्तों को बधाई! यह जीत 'राष्ट्र प्रथम' की भावना पर आधारित सकारात्मक और रचनात्मक छात्र राजनीति में युवाओं के निरंतर विश्वास और 'विकसित भारत' के विज़न में योगदान देने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।जीतने वाले उम्मीदवारों और इस जीत को संभव बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएँ।*

### अरुण जेटली समेत कई चर्चित नेता DUSU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं

- **अरुण जेटली:** 1974 में DUSU अध्यक्ष रहे और आगे चलकर केंद्र सरकार में देश के वित्त एवं रक्षा मंत्री बने (BJP)।
- **विजय गोयल:** 1977 में DUSU अध्यक्ष रहे और आगे चलकर केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने (BJP)।
- **अजय माकन:** 1985 में DUSU अध्यक्ष रहे और आगे चलकर केंद्र सरकार में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री बने (INC)।
- **अलका लांबा:** 1995 में DUSU अध्यक्ष रहीं और आगे चलकर दिल्ली विधानसभा में विधायक तथा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनीं (INC)।

### शौकीन के पिता बस कंडक्टर मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

शौकीन दिल्ली के पीरागढ़ी के रहने वाले हैं। उनके पिता बस कंडक्टर हैं और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उनके पिता चाहते थे कि वह UPSC की तैयारी करें, लेकिन शौकीन छात्र राजनीति में आना चाहते थे।

### शौक़ीन को NSUI के नाराज लोगों का साथ, जीत की 3 वजहें

- **NSUI से टिकट नहीं मिला, फिर भी मैदान नहीं छोड़ा:** शौकीन 4 साल NSUI से जुड़े रहे और छात्र राजनीति में एक्टिव थे। उन्होंने उपाध्यक्ष पद का टिकट मांगा था। संगठन की ओर से उनका नामांकन भी कराया गया, लेकिन बाद में उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। शौकीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।
- **ABVP-NSUI से अलग अपनी पहचान:** वे पहले से छात्र राजनीति में सक्रिय थे। इसलिए चुनाव में उनकी पहचान सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं, बल्कि कैंपस में सक्रिय छात्र नेता की भी थी। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो NSUI के नाराज कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया।
- **छात्रों के स्थानीय मुद्दों पर फोकस:** उनके प्रचार में हॉस्टल, छात्र सुरक्षा और कैंपस की सुविधाओं जैसे अहम मुद्दे रहे। इससे संगठन की राजनीति से अलग मुद्दों पर वोट मांगने में मदद मिली।

## 10 हजार करोड़ का लोहा चोरी का दावा:विधायक रिकेश सेन ने की CBI जांच की मांग

**शहर सत्ता/रायपुर।** भिलाई स्टील प्लांट (BSP) में हुई लोहा चोरी मामले में एक नया दावा किया जा रहा है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि प्लांट में पिछले 40 साल में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का लोहा चोरी हुआ है। हालांकि, पुलिस की ओर से इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। MLA ने कहा कि करोड़ों का लोहा चुराने वाले आरोपी को CBI ही पकड़ सकती है, उन्होंने CBI जांच की मांग की। आरोप है कि इस मामले में कई बड़े जनप्रतिनिधि और बीएसपी-CISF के कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। 2 दिन पहले इस मामले में रसमड़ा फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग और डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह की गिरफ्तारी की गई है। अब तक इस मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिनमें 3 जमानत पर बाहर हैं। 5 को अग्रिम जमानत मिल गई है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि मामले में गिरफ्तार लोगों को एक महीने के अंदर ही जमानत मिल गई। हालांकि उन्होंने बताया कि पुलिस जमानत के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, ताकि केस को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल एक संदेही और आरोपी के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन पिछले 40 साल में हुए करीब 10 हजार करोड़ रुपए के लोहा चोरी के मामले की पूरी जांच और आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।

## कुम्हारी में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की दबिश

**शहर सत्ता/रायपुर।** कुम्हारी क्षेत्र में कथित तौर पर संचालित एक अवैध गुटखा निर्माण इकाई पर रविवार को सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई की। रसमड़ा ग्राम, खुर्सीडीह और कुम्हारी स्टेशन चौक से जुड़े परिसर में की गई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दो मशीनों के साथ करीब 30 बोरा तैयार गुटखा जब्त किया है। टीम जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर रायपुर ले गई। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम रविवार को तीन वाहनों में मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही संबंधित परिसर में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण करने के साथ वहां रखी मशीनों, तैयार उत्पाद और अन्य सामग्री की जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार, जिस गोदाम में कार्रवाई की गई, उसके मालिक का नाम सुरेश गुप्ता बताया जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम गोदाम में मौजूद दस्तावेजों और बाकी सामग्री की भी जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई मशीनें और तैयार गुटखा जांच के महत्वपूर्ण हिस्से माने जा रहे हैं। करीब 30 बोरा तैयार उत्पाद मिलने के बाद टीम द्वारा इसके उत्पादन, भंडारण और संभावित वितरण से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।

## ऑटो में सामान छूटा तो नहीं होगी परेशानी

**शहर सत्ता/रायपुर।** जांजगीर-चांपा जिले में आने-जाने वाले यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सक्ती पुलिस ने ऑटो चालकों के पंजीयन की नई पहल शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत जिले में संचालित ऑटो चालकों का पुलिस पंजीयन किया जा रहा है। साथ ही पंजीकृत ऑटो पर ऐसा विशेष स्टीकर लगाया जा रहा है, जिसमें ऑटो से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज होगी। इससे यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा मिलने के साथ ही जरूरत पड़ने पर ऑटो चालक से सीधे संपर्क करना आसान होगा। रविवार को आत्मानंद स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले में संचालित ऑटो चालकों का पुलिस पंजीयन किया गया।

# झीरम की पूरी साजिश की जांच के लिए अड़ गई कांग्रेस

## भूपेश ने कहा-दिल्ली में उठाएंगे मुद्दा, आलाकमान से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर में शनिवार को झीरम घाटी मामले को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में अहम बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और झीरम हमले में शहीद हुए नेताओं के परिजन शामिल हुए। बैठक में एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद आगे की रणनीति और कानूनी विकल्पों पर चर्चा की गई। बैठक से पहले भी कांग्रेस ने फैसले को लेकर असंतोष जताया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में मौजूद परिवारों ने कहा कि एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद भी उनके आंसू नहीं थमे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि झीरम जैसे मामले में सिर्फ दोषियों को सजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि घटना के पीछे की पूरी साजिश और जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंचनी चाहिए।

### बैज बोले- छोटे स्तर के नक्सलियों पर कार्रवाई हुई

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की नजर में एनआईए कोर्ट का फैसला मुख्य रूप से उन आरोपियों तक सीमित है, जिन्हें पार्टी नक्सली संगठन के निचले स्तर का सदस्य मानती है। उनके अनुसार, इनमें वे लोग शामिल हैं जो झोला उठाने और सूचना तंत्र के तौर पर काम करते थे।

बैज ने कहा कि इन लोगों को जेल भेजा गया और कार्रवाई हुई, लेकिन झीरम मामले में जिन बड़े स्तर के लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उन तक जांच नहीं पहुंची। हालांकि, यह कांग्रेस की ओर से किया गया दावा है। अदालत ने ट्रायल का सामना कर रहे 10 आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद 16 सितंबर को उन्हें मृत्युदंड सुनाया है। मामले में 11 आरोपी ट्रायल पर थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

## फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा सर्व आदिवासी समाज

**शहर सत्ता/रायपुर।** PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। दिल्ली में झीरम के फैसले पर PC की जाएगी। सीनियर नेताओं से चर्चा कर न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर, सर्व आदिवासी समाज ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को कोया भवन में बस्तर संभाग के 6 जिलों दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर के समाज के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें फैसले पर चर्चा के साथ मामले में सजा पाए दोषियों के खिलाफ आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की रणनीति तय की गई। आदिवासी समाज के हर परिवार से 20-20 रुपए चंदा लिया जाएगा। इससे जुटने वाली राशि का इस्तेमाल हाईकोर्ट में मामले की पैरवी और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया में किया जाएगा।

**सर्व आदिवासी समाज केस लड़ने हर घर से ₹20 चंदा लेंगे**

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि, बैठक में 6 जिलों से समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने झीरम मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। समाज की ओर से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य पहलुओं पर भी काम किया जाएगा। प्रकाश ठाकुर ने कहा कि इस कानूनी लड़ाई के लिए समाज के स्तर पर आर्थिक सहयोग जुटाया जाएगा।

# महापौर बोलीं-बिना नल कनेक्शन वालों को जलकर का बिल क्यों?

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर नगर निगम में टैक्स और दूसरे शुल्क की वसूली को लेकर महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को दो टूक कहा है कि नियम के बिना किसी से पैसा नहीं लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि यूजर चार्ज में किस नियम के तहत ब्याज लगाया जा रहा है। अधिकारियों से कहा कि पहले अधिनियम और नियम ठीक से समझें, उसके बाद ही लोगों पर कर लगाएं। नगर निगम मुख्यालय में हुई राजस्व विभाग की बैठक में महापौर ने जलकर, यूजर चार्ज, बकाया टैक्स, पार्ट-पेमेंट, कॉलोनियों में टैक्स वसूली और निगम की लीज वाली संपत्तियों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पता चला कि कुछ ऐसे मकानों को भी जलकर का बिल भेजा जा रहा है, जहां नल कनेक्शन ही नहीं है। इस पर महापौर ने अधिकारियों से कहा कि जहां नल कनेक्शन नहीं है, वहां जलकर की वसूली न की जाए। उन्होंने साफ कहा कि निगम को अपना राजस्व बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए लोगों पर गलत तरीके से टैक्स का बोझ नहीं डाला जा सकता।

महापौर ने कहा कि जलकर और यूजर चार्ज पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बकाया पैसा एक साथ जमा करना मुश्किल हो तो पार्ट-पेमेंट की सुविधा भी आसान की जाए। ऑनलाइन पोर्टल पर भी नियमानुसार पार्ट-पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि लोगों को यह साफ पता होना चाहिए कि उनसे कितना टैक्स लिया जा रहा है और उसकी गणना किस आधार पर हुई है। कर के नियम और अलग-अलग स्लैब की जानकारी आसान भाषा में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए।

# यूपीआई पर शुल्क लगाने का कांग्रेस विरोध करती है - कांग्रेस

**शहर सत्ता/रायपुर।** यूपीआई पर शुल्क जनता की जेब पर सीधा डाका है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस यूपीआई को देश की डिजिटल क्रांति की पहचान बताकर प्रचारित किया गया। मोदी सरकार ने लोगों को ऑनलाइन लेने-देने की आदत लगाई गयी, आज उसी के इस्तेमाल पर आम जनता से लगभग 85 हजार करोड़ रू. से अधिक सालाना वसूलने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने पहले जनता को कैशलेस भुगतान की ओर धकेला, अब उसी व्यवस्था को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। देश का छोटा दुकानदार दिनभर में दर्जनों डिजिटल भुगतान करता है। यदि हर लेनदेन पर शुल्क लगा तो इसका सीधा असर उसके मुनाफे और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। दुकानदार तो मजबूरी के ग्राहक से वूसली करेगा। कांग्रेस, यूपीआई शुल्क का विरोध करती है तथा सरकार से इसको वापस लेने की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने यूपीआई लेनदेन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने को लेकर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। यूपीआई आज देश के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के लेनदेन का सबसे आसान और सुविधाजनक माध्यम बन चुका है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की कोई भी कोशिश सीधे आम जनता की जेब पर बोझ डालेगी।

## रायपुर में कांग्रेस के 74 ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दौर रविवार से रायपुर में शुरू हो गया। रायपुर संभाग के सभी 74 ब्लॉक अध्यक्ष इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। शिविर 20 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन संचालन, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, चुनावी तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनरों की टीम ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षण देगी। कांग्रेस की ओर से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रदेशभर में ब्लॉक अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर संभाग से पहले बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में प्रशिक्षण शिविर पूरे हो चुके हैं। रायपुर संभाग का शिविर इस प्रशिक्षण अभियान का अंतिम चरण है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होकर ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन से जुड़े मुद्दों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर मार्गदर्शन देंगे।

# तारा कोल ब्लॉक मामला : भूपेश बघेल ने दी CM साय को बहस की चुनौती

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को भिलाई टाउनशिप के कई गणेश पंडालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, सरकार इस मामले में जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय हसदेव अरण्य क्षेत्र के कई कोल ब्लॉकों को नीलामी से बाहर रखने की प्रक्रिया की गई थी। सीएम साय के 11 दिसंबर 2025 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, इसी पत्र के बाद तारा कोल ब्लॉक को दोबारा नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने की कार्रवाई आगे बढ़ी। बघेल ने कहा कि, उनके पास भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज हैं और मुख्यमंत्री के पास भी पत्र हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि मीडिया के सामने दोनों पक्ष दस्तावेज रखें और आमने-सामने चर्चा करें। उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इस मामले में खुली बहस होनी चाहिए।

### चुनाव अभी दूर, सीएम पद की दावेदारी पर चर्चा जल्दबाजी

कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए चार दावेदार होने संबंधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर भी भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव काफी दूर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अभी से चर्चा करना जल्दबाजी होगी।

### लोकल ट्रेन बंद होने से मजदूरों को परेशानी

भिलाई और आसपास के इलाकों में लोकल ट्रेन सेवा से रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों की समस्या का मुद्दा भी बघेल ने उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य लोग रोज ट्रेन से रायपुर, भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन करते हैं। लोकल ट्रेन सेवा बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बघेल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में डीआरएम को आवेदन देकर लोकल ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि रोजाना काम पर आने-जाने वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है।

### रेलवे के मुद्दों पर प्रदर्शन की चेतावनी

बघेल ने कहा कि, यदि रेलवे से जुड़े मुद्दों और स्थानीय स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रेलवे से जुड़े स्थानीय मुद्दों को उठाया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि आम यात्रियों की सुविधा से जुड़े इन मुद्दों पर रेलवे को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने लोकल ट्रेन सेवा और स्टेशनों पर ठहराव बहाल करने की मांग को लेकर आगे भी आवाज उठाने की बात कही।

# जल, जंगल, जमीन और अदानी को लेकर कांग्रेस खोलेगी मोर्चा

## राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जल-जंगल जमीनों को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस विष्णुदेव साय सरकार को जल, जंगल, जमीन और अदानी को दी गई खदानों के मामले में एक बड़ा आंदोलन करेगी। इस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जल-जंगल जमीनों को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा। बैज ने कहा; राहुल गांधी बस्तर भी आएंगे और सरगुजा भी आएंगे। बैज ने कहा कि विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि तारा कोल ब्लॉक आबंटित नहीं किया जाएगा तो यह कैसे नीलाम हुआ। तारा कोल ब्लॉक के जंगलों को बचाया जाएगा।

कांग्रेस इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। खदानों के आवंटन को लेकर सरकार को घेरते दिखे भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि, भारत सरकार ने खुद 40 खदानों को डि-नोटिफाइड किया। अब सवाल यह है कि विष्णुदेव साय ने दिसंबर 2025 में भारत सरकार को किसके स्वार्थ में, किस दबाव में पत्र लिखकर कहा कि तारा कोल ब्लॉक की नीलामी किया जाए। कांग्रेस शासनकाल में हसदेव की खदानें आबंटित किए जाने के आरोपों को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय बैठ जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डिबेट कर लेते हैं। अंबिकापुर में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, तारा कोल माइंस दिया गया है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया कि हसदेव क्षेत्र में और खदानें में खनन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार से 9 कोल ब्लॉकों को नीलामी से बाहर रखने हमने पत्र लिखा। भूपेश बघेल ने बताया कि कोल मिनिस्टर जोशी छत्तीसगढ़ आए तो मेरी मुलाकात हुई। हमने आग्रह किया कि यहां घना जंगल है, यहां से कोयला नहीं निकाला जाना चाहिए। यह हसदेव का कैचमेंट एरिया है। हमारा सिंचाई, थर्मल पावर भी प्रभावित होगा। आदिवासी हटाए जाएंगे।

## 25 सितंबर को सामूहिक वंदे मातरम गायन

**शहर सत्ता/रायपुर।** वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के अवसर पर 25 सितंबर को देशभर में सामूहिक गायन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भी कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़कर सामूहिक वंदे मातरम् गायन का नया विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास करना है। कार्यक्रम का नाम 'नमामि भारतम्' रखा गया है। छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारियां सरस्वती शिक्षा संस्थान के माध्यम से की जा रही हैं। रायपुर के साथ प्रदेश के अन्य विद्यालयों, उनके पोषित गांवों और वार्डों में भी सामूहिक गायन के कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से प्रतिभागियों का आगमन और पंजीयन शुरू होगा। कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन और अन्य आयोजन के बाद सुबह 11 बजे मुख्य सामूहिक गायन शुरू होगा। सुबह 11 बजे से 11 बजकर 3 मिनट 13 सेकंड तक सभी प्रतिभागी एक साथ वंदे मातरम् का गायन करेंगे। आयोजन को लेकर विद्यालय स्तर पर भी तैयारियां और अभ्यास चल रहा है। सामूहिक गायन के लिए 21 सितंबर को सुबह 11 बजे पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आयोजन को लेकर सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ प्रांत की ओर से विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

## ब्लैक करेंसी स्कैम, दो और आरोपी गिरफ्तार

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर में करोड़ों रुपए के 'वॉश-वॉश' ब्लैक करेंसी स्कैम (Black Currency Scam) मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के लोग केमिकल की मदद से काले कागज को असली नोट में बदलने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। इसी तरीके से सालिक-ग्रुप के डायरेक्टर से करीब 1.13 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में पुलिस पहले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब रामायण सिंह उर्फ अभिषेक सिंह और दीपक सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ रुपए से अधिक की नगदी बरामद की थी। इसके अलावा 20 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, नोट के आकार के काले कागज, कांच की प्लेट्स, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 4 करोड़ 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के साथ जब्त मोबाइल और उनमें मौजूद डिजिटल सामग्री की तकनीकी जांच की। इस दौरान आरोपियों के आपसी संपर्क और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली। इसी जांच में रामायण सिंह और दीपक सिंह की भूमिका सामने आई।

## उधारी के 30 लाख नहीं दिए, टीचर ने मार डाला

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर में एक टीचर ने ट्रेडिंग करने वाले अपने दोस्त की हत्या कर दी। चंद्रप्रकाश वर्मा ने अपने साथी शिवकुमार चंद्राकर को 30 लाख उधार दिए थे। इसके बदले वह ब्याज लेता था। पिछले तीन महीने से उसे ब्याज नहीं मिला था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पेशे से दोनों टीचर थे और एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। 17 सितंबर को आरोपी प्लानिंग के तहत उसे अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर सुनसान जंगल ले गया। वहां उसने हथौड़े से शिवकुमार का सिर फोड़ा और धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर मार डाला। मामला आरंग थाना क्षेत्र के महानदी तट के बनचरौदा के पास का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 17 सितंबर 2026 को आरंग पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बनचरौदा के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उसके सिर और चेहरे पर धारदार और कठोर वस्तु से गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान शिवकुमार चंद्राकर (46) के रूप में की। वह ग्राम रामपुर डंगनिया, थाना गोबरा नवापारा का रहने वाला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवकुमार चंद्राकर और चंद्रप्रकाश वर्मा दोनों ग्राम कुम्हारी के स्कूल में टीचर हैं। ग्रामीणों और गांव के चरवाहे ने पुलिस को बताया कि शिवकुमार को आखिरी बार चंद्रप्रकाश के साथ सफेद रंग की स्कूटी पर बनचरौदा की ओर जाते देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के CCTV फुटेज खंगाले।

# बिश्नोई गैंग के नाम से ढेबर परिवार को धमकी, 50 करोड़ मांगे

## अनवर-एजाज का नाम लेकर धमकाया, पुलिस ने शुरू की जांच

**रायपुर।** रायपुर में ढेबर परिवार को बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम लेकर धमकाया। फिर 50 करोड़ रुपए की मांग की है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि, ढेबर परिवार के एक कर्मचारी को फोन कर आरोपी ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने कहा कि फोन कॉल की जांच की जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है।

### कॉल की जानकारी जुटा रही पुलिस

पुलिस की टीम धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और कॉल से जुड़ी तकनीकी जानकारी जुटा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि, फोन किस जगह से किया गया और इसके पीछे कौन लोग हैं? पुलिस कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और बाकी टैक्टिकल सबूतों की जांच कर रही है। साथ ही परिवार से भी घटना को लेकर जानकारी ली जा रही है। फिलहाल, पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि, धमकी देने वाला वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या फिर गैंग का नाम लेकर परिवार को डराने की कोशिश की गई।

### रंजिश या किसी दूसरे विवाद की भी जांच

इसके अलावा व्यक्तिगत रंजिश या किसी दूसरे विवाद की संभावना को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, तकनीकी जांच के आधार पर धमकी देने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में सबूत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ढेबर परिवार की सुरक्षा और धमकी की गंभीरता को लेकर भी पुलिस हर स्तर पर जानकारी जुटा रही है।

### कमिश्नर ने की धमकी की पुष्टि

रायपुर कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने ढेबर परिवार के सदस्यों को धमकी दिए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कमिश्नर के मुताबिक, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कॉल वास्तव में बिश्नोई गैंग से आया था या किसी व्यक्ति ने गैंग का नाम लेकर धमकी दी। तकनीकी जांच के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

### सुरक्षा को लेकर भी जानकारी जुटा रही पुलिस

धमकी में 50 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मांगे जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की बात कहे जाने के बाद पुलिस परिवार की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस का फोकस धमकी भरे कॉल के स्रोत, मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान पर है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसी संगठित गिरोह की भूमिका है या फिर उसके नाम का इस्तेमाल कर परिवार को धमकाया गया।

## छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की नई तैयारी

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को अब सिर्फ रोजगार देने तक सीमित रखने के बजाय आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबी-जी राम-जी के तहत अनुमेय कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। अब मिशन के तहत 318 की जगह 375 तरह के काम कराए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वीबी-जी राम-जी के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 3,354.85 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन किया गया है। मिशन के तहत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर भी 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अनुमेय कार्यों की संख्या बढ़कर 375 होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का दायरा बढ़ेगा। उनका कहना है कि मिशन का उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ऐसे काम कराना है जिनसे गांवों में लंबे समय तक उपयोगी रहने वाली परिसंपत्तियां तैयार हों। इन कार्यों के जरिए जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क, स्कूल, पंचायत भवन, आजीविका केंद्र और सामुदायिक सुविधाओं के साथ कृषि और पशुपालन से जुड़ी अधोसंरचना को भी मजबूत किया जाएगा। वीबी-जी राम-जी के तहत 375 कार्यों को चार मुख्य श्रेणियों और 30 उप-श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 68 तरह के व्यक्तिगत कार्य, 99 तरह के मरम्मत एवं रखरखाव के काम और समूह व सामुदायिक उपयोग से जुड़े विभिन्न कार्य शामिल हैं। ग्रामीणों को इन कार्यों की जानकारी आसानी से मिल सके।

# रायपुर में संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली निकली




**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर में रविवार को जेन-जी (Gen-Z) युवा वर्ग की ओर से संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली निकाली गई। युवा संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर नारे लगाते हुए राजभवन की ओर बढ़े। रैली में शामिल युवाओं ने पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने और आरक्षण रोस्टर की पुनर्स्थापना की मांग रखी। आयोजकों ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लंबे समय से खाली बैकलॉग पदों को भरा जाना चाहिए। आरक्षण से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन करने की मांग भी की गई।

रैली में शामिल युवाओं ने पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने और आरक्षण रोस्टर की पुनर्स्थापना की मांग रखी।

रैली में शामिल युवाओं ने पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने और आरक्षण रोस्टर की पुनर्स्थापना की मांग रखी। राजभवन पहुंचने से पहले पुलिस ने रैली को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं रुक गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने एससी-एसटी उपयोजना और आदिवासी उपयोजना के बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी रखी गई।

प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर ठेका, आउटसोर्सिंग और प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था कि ऐसी भर्ती व्यवस्था में आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी रखी गई।

# एनालॉग पनीर बेचने वालों पर खाद्य विभाग का शिकंजा

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच नकली और एनालॉग पनीर के कारोबार पर खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) और विभिन्न राज्यों के खाद्य विभागों की टीमें लगातार जांच और छापेमारी कर रही हैं। उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। असली पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों में भी पनीर की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। त्योहारी मांग बढ़ने के कारण विभाग ने निगरानी और तेज कर दी है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) देशभर में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर 24 सितंबर को सभी राज्यों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की टीमें दुकानों, डेयरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान कई जगहों से संदिग्ध और नकली पनीर जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है।

# 20 साल के हिसाब से सड़क, सिंचाई व डिजिटल नेटवर्क का प्लान

## लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में अब सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और डिजिटल कनेक्टिविटी की योजनाएं अलग-अलग नहीं, बल्कि अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एकीकृत तरीके से तैयार की जाएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत दीर्घकालिक समग्र कार्ययोजना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के रोड नेटवर्क का 20 साल का मास्टर प्लान तैयार होगा। इसमें वर्तमान स्थिति के साथ भविष्य में बनने वाले विकास क्षेत्रों और उनकी कनेक्टिविटी की जरूरतों का भी आकलन किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है। रोड नेटवर्क के मास्टर प्लान में यह स्पष्ट होगा कि अगले दो दशक में कहां नई सड़कें बनेगी, किन मार्गों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और किन क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना होगा। इसके आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाएगी। हर साल का अलग एक्शन प्लान: 20 साल के मास्टर प्लान के साथ हर वर्ष का एक्शन प्लान भी बनेगा। इसमें उस साल होने वाले काम, प्राथमिकता, संसाधन और समय-सीमा तय होगी। बड़ी परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश समेत नए फंडिंग मॉडल की संभावनाओं पर भी विचार होगा। इसी तरह दूसरे राज्यों की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।

### लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाशेंगे

राज्य में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। सड़क और रेल समेत अलग-अलग परिवहन माध्यमों को जोड़कर माल परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी परियोजनाएं चिन्हित होंगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सड़क के साथ ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क के लिए भी एक साथ योजना बनाई जाएगी। यानी किसी क्षेत्र में बड़ी सड़क या अन्य कनेक्टिविटी परियोजना प्रस्तावित होने पर वहां भविष्य में बिजली, पानी और डिजिटल नेटवर्क की जरूरतों का भी आकलन किया जाएगा।

### ... लॉजिस्टिक्स हब महत्वपूर्ण क्यों

लॉजिस्टिक्स हब एक ऐसा बड़ा केंद्र होता है, जहां सामान के भंडारण, पैकेजिंग, छंटाई, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। यहां सड़क, रेल और जरूरत के अनुसार हवाई या जल परिवहन जैसे अलग-अलग माध्यमों को आपस में जोड़ा जाता है। इससे सामान को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और उसकी आवाजाही तेज होती है।

# गणेश उत्सव में पुलिस की सख्ती नॉर्थ जोन में 25 लोगों पर कार्रवाई

## धरसींवा में 57 जेल भेजे गए; ड्रोन से भी निगरानी

**शहर सत्ता/रायपुर।** गणेश उत्सव और आगामी त्योहारों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। शहर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। नॉर्थ जोन पुलिस ने पंडरी, उरला, गुढ़ियारी और खमतराई थाना क्षेत्रों में 25 लोगों पर कार्रवाई हुई, जबकि खम्हारडीह पुलिस ने 8 गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाने बुलाकर चेकिंग और पूछताछ की।

4वहीं, धरसींवा में एक सप्ताह में 57 लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया। गुढ़ियारी क्षेत्र में ड्रोन को सुरक्षा की 'तीसरी आंख' के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र में गणेश पंडालों के आसपास अड्डेबाजी, नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

गणेश उत्सव और आगामी त्योहारों के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नॉर्थ जोन पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। पुलिस उपायुक्त दीपमाला कश्यप के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे के पर्यवेक्षण में प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के जरिए हवाई निगरानी की जा रही है। लोगों की आवाजाही, भीड़ की स्थिति और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है।

## संपादकीय

सुकांत राजपूत

# लैंगिक समानता में भारत 131वें स्थान पर क्यों?

किसी भी समाज में लैंगिक समानता विकास का महत्त्वपूर्ण आधार होती है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक अवसरों में पुरुषों के समान अवसर मिलना केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति से भी जुड़ा है। इसके बावजूद भारत लैंगिक समानता के मामले में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से बुधवार को जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक-2026 में भारत 131वें स्थान पर बरकरार रहा। कुल 145 देशों की सूची में भारत से नीचे केवल 14 देश हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति में अभी सुधार की कितनी गुंजाइश है।

अहम सवाल यह है कि जब भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है, तो लैंगिक समानता की कतार में वह पीछे क्यों खड़ा है? विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समाज में संसाधनों और सुविधाओं के बंटवारे में संतुलन तथा व्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति 64.5 फीसद रही, लेकिन यह वैश्विक औसत से कम है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में अंकों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन देश की वैश्विक रैंकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर वर्ष 2006 के बाद से भारत में लैंगिक समानता में 4.3 फीसद अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

भारत की स्थिति को समझने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि समस्या केवल महिलाओं की शिक्षा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर उप सूचकांक में भारत को समानता के मामले में 41.2 फीसद अंक मिले हैं। पिछले सूचकांक की तुलना में इसमें 0.5 फीसद का सुधार हुआ है, लेकिन वर्ष 2013 में मिले सबसे अच्छे परिणाम से यह 3.5 फीसद अंक कम है। देश में सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रोजगार से बाहर रह जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं का काम अक्सर कृषि और पारिवारिक गतिविधियों तक सीमित रहता है, जिसका पूरा आर्थिक मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पाता।

एक और समस्या आय का अंतर है। समान स्तर के काम के बावजूद महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में कम रहने की समस्या अब भी बनी हुई है। इसका अर्थ है कि शिक्षा हासिल करने के बावजूद महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों तक समान पहुंच अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में पिछले दो दशकों में श्रमिक कार्यबल में भागीदारी की समानता में मामूली सुधार हुआ है और वर्ष 2026 में यह 44.1 फीसद रहा। महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसरों का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। जो महिलाएं शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, शीर्ष पदों पर उनकी तैनाती बहुत कम हो पाती है। इसलिए जरूरी है कि उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, जिनके कारण यह अंतर बना हुआ है।

# विकास दौड़ रहा है, रायपुर जाम में खड़ा है डबल डेकर फ्लाइओवर भी कम पड़ जाए !

रायपुर में यातायात केवल यात्रा नहीं है। यह जीवन-दर्शन है। किसी ने पूछा—"रायपुर कितना विकसित हो गया?" जवाब मिला—"इतना कि अब जाम में खड़े रहने के लिए भी पर्याप्त वाहन उपलब्ध हैं।"

शहर में जनसंख्या बढ़ी। वाहन बढ़े। बाजार बढ़े। मकान बढ़े। कॉलोनियां बढ़ीं। लेकिन सड़कें बेचारी अपनी पुरानी उम्र में ही खड़ी रहीं। उन्हें देखकर लगता है कि विकास ने उनसे कहा—

"तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे ऊपर से निकल जाऊंगा।" और विकास ने फ्लाईओवर बना लिया।

एक फ्लाईओवर खत्म हुआ तो दूसरा प्रस्तावित हो गया। एक लिंक रोड बनी तो दूसरी की जरूरत महसूस हुई। समस्या का समाधान निकला नहीं, समस्या ने अपने अगले संस्करण की घोषणा कर दी।

रायपुर में कभी डबल डेकर बस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब लगता है कि डबल डेकर फ्लाईओवर की जरूरत जरूर पड़ सकती है। एक फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर—नीचे जाम रहे तो ऊपर से निकल जाइए, और ऊपर भी जाम हो जाए तो फिर अगली मंजिल के बारे में सोचिए। आखिर विकास भी तो रुकना नहीं चाहिए!

नीचे पैदल आदमी पूछेगा—"भाई साहब, जाना किधर है?" ऊपर से कार वाला जवाब देगा—"पहले यह बताइए कि मैं किस लेयर में हूं!" दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े शहरों में डबल डेकर फ्लाइओवर बने हैं। रायपुर भी महानगरीय जीवन की उसी दिशा में बढ़ रहा है। फर्क बस इतना है कि वहां जाम पुराना है और हमारे यहां जाम नया होते हुए भी पुराना दिखाई देता है। हमारे यहां विकास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह समस्या को खत्म नहीं करता, उसे बड़ा कर देता है। पहले छोटा जाम था। फिर बड़ा जाम हुआ। अब बहुस्तरीय जाम की तैयारी है।

कल को कोई पूछेगा—"रायपुर में सबसे ऊंची इमारत कौन-सी है?"

जवाब आएगा—"जहां सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है।"

रायपुर अब राजधानी है। राजधानी होने के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। आसपास के कस्बों और गांवों से लोग आते हैं। कारोबार बढ़ा। सरकारी दफ्तर बढ़े। शिक्षा, इलाज, खरीदारी और रोजगार के लिए लोगों का आना-जाना बढ़ा। स्वाभाविक है कि यातायात का दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम केवल सड़क बनाकर यातायात की समस्या हल कर सकते हैं? शायद नहीं। क्योंकि सड़क जितनी चौड़ी होगी, वाहन उतने ही बढ़ेंगे। वाहन बढ़ेंगे तो फिर सड़क छोटी पड़ जाएगी। फिर सड़क चौड़ी होगी। फिर वाहन बढ़ेंगे। यह ऐसा ही है जैसे पेट की बीमारी का इलाज करने के लिए पैंट का साइज बढ़ाते जाना। रायपुर को केवल और सड़कें नहीं चाहिए। उसे ऐसी यातायात व्यवस्था चाहिए जिसमें सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो, पैदल चलने वाले सुरक्षित हों, साइकिल के लिए जगह हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, बाजारों और कार्यालयों की यातायात योजना बने और शहर का विकास केवल सड़क के ऊपर नहीं, सड़क के चारों तरफ भी योजनाबद्ध हो। वरना फ्लाईओवर बनते रहेंगे और नीचे जाम भी बनता रहेगा।

हम कहेंगे—"देखिए, कितना विकास हुआ!" जाम में फंसा आदमी कहेगा—"हां, दिख रहा है। सामने वाले चौराहे तक पहुंचने में बस पैंतालीस मिनट और लगेंगे।" फिर कोई अधिकारी बताएगा—"शहर को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।"

नागरिक पूछेगा—"भविष्य कब आएगा?"

अधिकारी कहेगा—"बहुत जल्दी।"

नागरिक घड़ी देखेगा। सामने लाल बत्ती जल रही होगी। वह फिर पैंतालीस मिनट इंतजार करेगा और रायपुर विकास की अगली घोषणा का इंतजार करता रहेगा। क्योंकि यहां विकास कभी रुकता नहीं। बस यातायात रुक जाता है। कल को शायद गणेश पंडाल भी मल्टीलेवल होंगे, पार्किंग भी मल्टीलेवल होगी और जाम भी। तब गणेश जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी—

"बप्पा, इस बार मोदक बाद में देना, पहले रायपुर के ट्रैफिक का विसर्जन करवा देना।"

रायपुर में बढ़ती भीड़ का आलम यह है कि गणेश पंडालों में लोगों को डराने और मनोरंजन करने के लिए खड़े किए गए भूत भी अब खुद डरे हुए नजर आने लगे हैं। जिन भूतों को देखकर लोग चीखने और रोमांचित होने आते थे, वे ही भीड़ और ट्रैफिक देखकर सहमे खड़े हैं।

एक भूत दूसरे से कह रहा है—

"हम तो लोगों को डराने आए थे, यहां तो भीड़ ही हमसे ज्यादा डरावनी निकली!"

दूसरा बोला—

"पहले लोग हमें देखकर रास्ता बदलते थे, अब हमें ही रास्ता नहीं मिल रहा!"

रायपुर में जाम इतना बढ़ गया है कि भूत भी सोचने लगे हैं—डराना किसे है और डरना किससे है! भूतों ने आखिरकार समिति से कह दिया, "हमें डरावना बनाने की जरूरत नहीं है। रायपुर का ट्रैफिक दिखा दीजिए, लोग अपने आप डर जाएंगे।"

**कॉलम - खुरचन**

द्वारा- हरिदास

# सेवा संकल्प अभियान : 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत

डॉ. ओम प्रकाश डहरिया
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

किसी बच्चे की आंखों में देखें तो वहां केवल बचपन नहीं दिखाई देगा, बल्कि वहां आने वाले भारत की तस्वीर दिखाई देगी। किसी की आंखों में अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना है, कोई डॉक्टर बनकर गांव के लोगों की सेवा करना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनकर नई खोज करना चाहता है, तो कोई अपने गांव में ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसके साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार का अवसर मिले और भविष्य सुनिश्चित हो सके। वहीं किसी बच्चे का सपना खेल के मैदान से जुड़ा है तो किसी का खेत, तकनीक, शिक्षा, कला या उद्यमिता से। भारत के करोड़ों बच्चों की आंखों में पल रहे यही अनगिनत सपने मिलकर वर्ष 2047 के विकसित भारत की नींव रख रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और राष्ट्रनिर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' की दूसरी पहल '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत' इसी भविष्य को समझने और उसे आकार देने का संकल्प है। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि उस पीढ़ी के प्रति विश्वास का संदेश है, जो वर्ष 2047 में विकसित भारत की जिम्मेदारी संभालेगी। आज जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वही कल भारत के वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, सैनिक, खिलाड़ी, उद्यमी, शोधकर्ता और नीति-निर्माता होंगे।

विकसित भारत की यात्रा की शुरुआत इसलिए स्कूल की कक्षा से होती है। एक बच्चे के हाथ में किताब होती है, लेकिन उसी किताब के पन्नों में उसके भविष्य की पूरी दुनिया छिपी होती है। शिक्षा को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित रखने के बजाय बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कौशल, तकनीकी समझ और नवाचार की भावना विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास आने वाले भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। पीएम श्री स्कूल इसी बदलती सोच का उदाहरण हैं, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ प्रयोग, खेल, कला, तकनीक और अनुभव के माध्यम से सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

लेकिन भारत के सपनों की असली ताकत तब सामने आएगी, जब विकास की रोशनी उन बच्चों तक भी पहुंचेगी, जिनके घर दूरस्थ गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और वनांचलों में हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्य में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एकलव्य आवासीय विद्यालयों ने जनजातीय समाज के अनेक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर दिए हैं। जिन बच्चों के लिए कभी बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करना दूर का सपना था, उनके लिए आवासीय विद्यालय शिक्षा और बेहतर भविष्य की नई राह बन रहे हैं।

इन विद्यालयों की कक्षाओं में बैठा कोई बच्चा जब पहली बार बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता है, तो उसके साथ केवल उसका अपना सपना नहीं होता। उसके पीछे माता-पिता की उम्मीदें होती हैं, परिवार की वर्षों पुरानी आकांक्षाएं होती हैं और पूरे समाज की बदलती तस्वीर होती है। एक बच्चे की सफलता उसके परिवार को यह विश्वास देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, प्रतिभा को अवसर मिले तो मंजिल हासिल की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रयास आवासीय विद्यालय भी विद्यार्थियों के सपनों को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के सामने उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल रहे हैं। जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन और तैयारी का वातावरण इन विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास देता है। यह बदलाव केवल शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस सोच का विस्तार है जिसमें बच्चे की प्रतिभा को उसके गांव, परिवार या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और मेहनत से पहचाना जाता है।

वर्ष 2047 के भारत की तस्वीर केवल ऊंची इमारतों, आधुनिक शहरों और नई तकनीकों से नहीं बनेगी। उसकी असली पहचान उस बच्चे के आत्मविश्वास से होगी, जो कह सके कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। विकसित भारत का अर्थ तब और व्यापक होगा, जब देश का युवा रोजगार की तलाश करने के साथ रोजगार पैदा करने की क्षमता भी रखेगा। शिक्षा के साथ कौशल, नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी दक्षता युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करने की शक्ति देगी।

आज का विद्यार्थी कल का केवल नौकरी तलाशने वाला युवा नहीं, बल्कि नया विचार देने वाला शोधकर्ता, नई तकनीक बनाने वाला नवाचारी, अपना व्यवसाय खड़ा करने वाला उद्यमी और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने वाला परिवर्तनकारी नागरिक बन सकता है। यही वह सोच है जो विकसित भारत के संकल्प को व्यापक अर्थ देती है।

'25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत' इसलिए केवल बच्चों के भविष्य की बात नहीं करता, यह पूरे देश के भविष्य की बात करता है। आज किसी स्कूल की प्रयोगशाला में प्रयोग करता बच्चा, किसी एकलव्य विद्यालय में पढ़ता जनजातीय विद्यार्थी, प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता युवा और अपने गांव में भविष्य का कोई नया रास्ता तलाशता विद्यार्थी-ये सभी 2047 के भारत की बदलती तस्वीर के गवाह होंगे।

इन बच्चों के सपनों को अवसर देना ही राष्ट्रनिर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। क्योंकि किसी देश की वास्तविक शक्ति उसके संसाधनों में नहीं, उसकी नई पीढ़ी की कल्पनाशक्ति और सामर्थ्य में होती है। जब करोड़ों बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके भीतर सवाल पूछने की हिम्मत होगी, प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब भारत की विकास यात्रा और अधिक मजबूत होगी।

वर्ष 2047 का विकसित भारत आज से ही बनना शुरू हो चुका है। उसकी नींव आज की कक्षाओं में रखी जा रही है, उसकी उम्मीदें बच्चों की आंखों में पल रही हैं और उसकी दिशा युवाओं के सपनों से तय होगी। इसलिए जरूरी है कि देश का कोई बच्चा अवसर के अभाव में अपने सपने को छोटा न करे। उसके सपनों की उड़ान जितनी ऊंची हो, भारत का आकाश उतना ही खुला हो।

क्योंकि 25 करोड़ बच्चों के सपने केवल 25 करोड़ व्यक्तिगत सपने नहीं हैं। ये 25 करोड़ संभावनाएं हैं, 25 करोड़ नई दिशाएं हैं और 25 करोड़ ऐसे भविष्य हैं, जिनसे मिलकर भारत का नया अध्याय लिखा जाएगा। जब इन सपनों को शिक्षा, अवसर, कौशल और सही दिशा का सहारा मिलेगा, तब वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल एक लक्ष्य नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों बच्चों की आंखों में दिखाई देने वाला साकार सपना होगा। यही 'सेवा संकल्प अभियान' बच्चों के सपनों के भारत का वास्तविक भाव है।

## इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन

**नई दिल्ली।** पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया है. अलीमा लगातार इमरान के साथ हो रहे जेल में बर्ताव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात कही थी. उसी के कुछ दिन बाद शहबाज सरकार की पुलिस ने यह एक्शन लिया है. लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत दिए गए आदेश के मुताबिक, अलीमा खान को 30 दिन के लिए हिरासत में या फिर गिरफ्तार रखा जा सकता है. आदेश में कहा गया कि आज डीसी लाहौर की अध्यक्षता में जिला खुफिया कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें फैसला हुआ की शहर में शांति कायम करने के लिये इमरान खान की बहन अलीमा खानम को हिरासत में लिया जाए. खबर है कि पंजाब पुलिस ने अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती हिरासत में लिया है. अभी यह जानकारी नहीं मिली है, वह और उनके ड्राइवर किस जगह पर ले जाए गए हैं. साथ ही उनकी गिरफ्तारी की वजह की भी जानकारी नहीं मिल पाई है. उनके समर्थन मांग कर रहे हैं, उनके परिवार और कानूनी प्रतिनिधियों को उनके ठिकाने, उन्हें हिरासत में लेने के कानूनी आधार और उस मामले के बारे में बताया जाए, जिसके तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है.

## विजय को कम से कम एक साल मौका दें: प्रकाश राज

**नई दिल्ली।** अभिनेता प्रकाश राज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए और केवल 120 दिन के आधार पर उसके प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जाना चाहिए. प्रकाश राज ने कहा कि कम से कम एक साल तक सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए. मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने कहा कि विजय सिर्फ उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, बल्कि उन लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए सरकार को काम करने का समय मिलना चाहिए.उन्होंने कहा कि विजय को लेकर उनके मन में पहले से कई सवाल और संदेह थे और उन्होंने चुनाव से पहले भी अपनी बात रखी थी.

लेकिन अब जब विजय की पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बना ली है, तो केवल 120 दिन बाद किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा. प्रकाश राज ने साफ कहा कि अगर एक साल बाद भी सरकार लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती है, तो वह सरकार से सवाल जरूर करेंगे.

## पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला

**नई दिल्ली।** पश्चिम बंगाल के जादवपुर इलाके में शनिवार रात राजनीतिक तनाव की स्थिति बन गई. विजयगढ़ समेत आसपास के इलाकों में कई राजनीतिक कार्यालयों और नेताओं से जुड़े ठिकानों पर तोड़फोड़ की शिकायत सामने आई है. इनमें पूर्व TMC विधायक देबब्रत मजूमदार के घर और कार्यालय को भी निशाना बनाए जाने का आरोप है. घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, जादवपुर के कई वार्डों में मोटरसाइकिलों पर आए लोगों के समूह ने कुछ CPI(M) कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की. इस दौरान पार्टी के झंडे हटाने और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं.

# राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर भड़की BJP

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है. कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शख्स राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की मिमिक्री करता दिख रहा है और राहुल गांधी इसे एंजॉय करते दिख रहे हैं. इसी वीडियो को री-पोस्ट करते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है. किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी बन गई है इसी के चलते वो हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं. उन्होंने आगे लिखा- RIP. ये मिमिक्री वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां पीएम मोदी का मजाक उड़ाया गया.

### बुजुर्ग महिला के अपमान का आरोप

राहुल गांधी के मंच पर मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मनी ने पीएम मोदी की मिमिक्री के दौरान बुजुर्ग महिला के लिए कुर्सी मांगे जाने का मजाक उड़ाया. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे बुजुर्ग मां का अपमान करार दिया है. उन्होंने लिखा, 'एक तरफ सम्मान और अपनापन, दूसरी तरफ बुजुर्ग मां का मजाक.'

### क्या बोलीं स्मृति ईरानी

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वीडियो को रि-पोस्ट करते हुए लिखा, "जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है." इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं बल्कि ट्रोल्स के नेता हैं. देश के शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मंच पर पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान हुआ है. मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अक्सर राहुल गांधी ऐसा करते हैं. अगर छात्रों का आयोजन था तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी. उनसे सवाल और जवाब कर सकते थे, लेकिन इस तरह पीएम मोदी की मिमिक्री करना और एक बुजुर्ग महिला का अपमान किया जाना गलत है.

### क्या बोले गजेंद्र शेखावत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे शर्मनाक करार दिया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मां के अपमान पर हंसकर राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक संस्कार पूरे देश के सामने रख दिए हैं. कांग्रेस का ये राजकुमार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तीखे प्रहार भी हो सकते हैं लेकिन किसी की दिवंगत मां पर अमर्यादित टिप्पणी और उस पर उपहास की राजनीति भारतीय समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पीएम मोदी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा, "किसी का सरनेम चुराया जा सकता है, संस्कार नहीं."

## PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर

**नई दिल्ली।** पाकिस्तान सेना में वरिष्ठ स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. सितंबर के तीसरे सप्ताह में सामने आई नियुक्तियों के मुताबिक मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वाराइच को पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का नया महानिदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही ISI और सेना की कई अहम कमान में भी नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. इस फेरबदल में मेजर जनरल मोहम्मद शमरियाज खान की नियुक्ति भी खास है. उन्हें ISI के DG-S पद की जिम्मेदारी दी गई है. रिपोर्टों के मुताबिक इससे पहले वह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे. हालांकि उनकी नई खुफिया जिम्मेदारी से जुड़ी कई डिटेल जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सीमित है. पाकिस्तान सेना में हुए बदलाव के तहत मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वाराइच को Director General Military Intelligence (DGMI) नियुक्त किया गया है. वह इससे पहले 7 इन्फैंट्री डिवीजन समेत फील्ड कमान से जुड़ी जिम्मेदारियों में रहे हैं. नई नियुक्ति के साथ वह पाकिस्तान के सैन्य खुफिया ढांचे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे.मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान सेना की अपनी सैन्य खुफिया व्यवस्था है।

# हामिद अंसारी के बयान पर घमासान इमाम बोले- माहौल खराब न करें

**नई दिल्ली।** पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को लेकर दिए बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है. अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा था कि भारत के लिए असली खतरा साम्यवाद नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है. उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई.

इसके बाद अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉ. उमर अहमद इलियासी ने अंसारी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि अंसारी मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल कर अपना प्रभाव वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान देश का माहौल बिगाड़ने वाली बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं. इमाम डॉ. उमर अहमद इलियासी ने अंसारी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "जब हामिद अंसारी सत्ता में थे और बड़े पदों पर रहे, तब वे खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते थे. अब उन्हें मुस्लिम समुदाय की याद आ रही है. इलियासी ने कहा कि मुस्लिम समाज अब अंसारी के बारे में सवाल नहीं कर रहा है और उनके मुताबिक अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को इस तरह इस्तेमाल कर उन्हें उकसाने वाले बयान देना देश के माहौल को खराब कर सकता है. इलियासी ने इसे देश का माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश तक बताया."

# यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला

**नई दिल्ली।** यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया है. इसमें एक साथ एक हजार से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है. अलजजीरा के मुताबिक, रूस में संसदीय चुनावों के आखिरी दिन, राजधानी समेत मॉस्को इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है. एक बड़ी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा है कि 1600 से ज्यादा ड्रोन को रोका गया है. इनमें 450 राजधानी की ओर बढ़ रहे थे. इधर, यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रातभर कीव पर रूस ने हमले किए, इसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है. इनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. ये हमले

ऐसे वक्त हुए हैं, जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ लंबी दूरी के हमले तेज कर रहे हैं.मॉस्को के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए, इस हमले को सबसे बड़ा बताया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के दो अलग-अलग हमलों में एक 44 साल की महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है. वोरोब्योव ने कहा है कि एक 21 मंजिला बिल्डिंग से ड्रोन टकराने से लगी आग के कारण 400 लोगों को बाहर निकाला गया. हमलों के दौरान मॉस्को ऑयल रिफाइनरी की एक सुविधा को नुकसान पहुंचा है. इमरजेंसी सर्विस मौके पर मौजूद हैं.

## मक्का पैक्ट को लेकर पाकिस्तान पर बरसे US के पूर्व NSA

**नई दिल्ली।** सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एच.आर. मैकमास्टर ने मक्का रक्षा समझौते में पाकिस्तान और तुर्किये की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के इरादों और समझौते को लागू करने की उसकी क्षमता पर संदेह जताया. साथ ही उन्होंने तुर्किए की मौजूदा सरकार की नीतियों को लेकर भी अपनी आलोचनात्मक राय रखी. मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने हस्ताक्षर किए थे. समझौते के अनुसार तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा. तुर्किये ने बाद में इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सामूहिक रक्षा व्यवस्था के तकनीकी रूप से समान बताया था. मैकमास्टर ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि अब यह देखना होगा कि वह इस समझौते की शर्तों को वास्तव में लागू करता है या नहीं. पाकिस्तान की नीतियों में एक साथ अलग-अलग दिशाओं में काम करने की क्षमता दिखाई देती रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मक्का समझौता काफी हद तक दिखावटी हो सकता है और इसके पीछे सऊदी अरब से पाकिस्तान की ओर आर्थिक मदद का प्रवाह बनाए रखना होगा।

# 'मातोश्री' जाकर दिशा के पिता ने थमाया 500 करोड़ का नोटिस

**मुंबई।** दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। शनिवार (19 सितंबर) को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अपने वकीलों के साथ मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आवास 'मातोश्री' पहुंचे। उन्होंने आदित्य ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के मानहानि दावे से संबंधित कानूनी नोटिस दिया। नोटिस आदित्य ठाकरे की ओर से उनके वकील ने स्वीकार किया। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे ने पूरे मामले में एक बड़ा कदम उठाया है।

नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, "सभी मीडिया मित्र... दिशा सालियान मामले में कानून को अपना काम करने दें! इस पर रोज टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। धन्यवाद।"सतीश सालियान की ओर से दिए गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस में आदित्य ठाकरे के साथ पूर्व गृह मंत्री व एनसीपी (शरद पवार) नेता अनिल देशमुख का भी नाम है। आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ का नोटिस मिलने पर संजय राउत भड़के, कहा- सब नौटंकी है, दिशा का दुर्भाग्य कि ऐसे पिता मिले

### आदित्य ठाकरे बोले- मैं दिशा सालियान को नहीं जानता

आदित्य ठाकरे ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि दिशा सालियान की मौत से उनका कोई लेना-देना नहीं है और वे कभी उनसे नहीं मिले। उन्होंने दिशा की मौत से अपने नाम को जोड़ने के प्रयासों को राजनीतिक और व्यक्तिगत वजहों से चलाया जा रहा अभियान बताया था।पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी चेतावनी दी है कि यदि उनके परिवार का चरित्र हनन करने की कोशिशें बंद नहीं हुईं, तो वे कानूनी कदम उठाएंगे। जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का इस्तेमाल ठाकरे परिवार के खिलाफ कीचड़ उछालने के लिए 'कठपुतली' के रूप में किया जा रहा है। मामले पर शिवसेना (यूबीटी) के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने सतीश सालियान को लेकर आरोप लगाया कि कुछ लोग ठाकरे परिवार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राउत ने यह भी दावा किया कि सतीश सालियान को दूसरे लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है।

### अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सता रहा डर

# चीन चुरा लेगा F-35 की तकनीक

**नई दिल्ली।** अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 अत्याधुनिक एफ-35 लड़ाकू विमान देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. विमानों और एक अतिरिक्त इंजन वाली इस डील की कीमत करीब 24.3 अरब डॉलर यानी लगभग 2430 करोड़ डॉलर बताई गई है. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस सौदे से सऊदी अरब की मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता मजबूत होगी. हालांकि, इस डील को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कुछ रिपोर्टों में चीन के संभावित तकनीकी पहुंच बनाने को लेकर चिंता जताई गई है. अगर विमानों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तय प्रक्रिया के तहत पूरी होती है, तो सऊदी अरब इजराइल के बाद पश्चिम एशिया का दूसरा देश होगा, जिसके पास एफ-35 लड़ाकू विमान होंगे.

### चीन के हाथ लग सकती है एफ-35 की तकनीक?

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्टों में आशंका जताई गई है कि सऊदी अरब को एफ-35 मिलने के बाद चीन इस लड़ाकू विमान की तकनीक हासिल करने की कोशिश कर सकता है. रिपोर्टों में सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है.पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक विस्तृत रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि एफ-35 से जुड़ी संवेदनशील तकनीक वाले ठिकानों को अमेरिका और सऊदी अधिकारी किस तरह सुरक्षित रख पाएंगे. रिपोर्ट में खास तौर पर चीन के सैन्य अधिकारियों की सऊदी सैन्य ठिकानों तक पहुंच और वहां इस्तेमाल हो रही चीनी तकनीक को लेकर चिंता जताई गई है.

### सऊदी सैन्य ठिकानों तक चीनी पहुंच पर चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के साथ चीन की रक्षा साझेदारी है और चीनी सैन्य कर्मियों की सऊदी अरब के कुछ सैन्य ठिकानों तक पहुंच रही है. इसके अलावा सऊदी अरब के दूरसंचार और रक्षा ढांचे में चीनी तकनीक के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है. पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जगहों पर एफ-35 की संवेदनशील तकनीक और उससे जुड़ी प्रणालियां रखी जाएंगी, वहां पहुंच केवल अमेरिकी और सऊदी अधिकारियों तक सीमित होनी चाहिए. अमेरिकी अधिकारियों को खास तौर पर एफ-35 के उन्नत रडार, निगरानी और अन्य संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा की चिंता है. अमेरिकी रिपोर्टों में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या सऊदी अरब चीनी सेना और खुफिया अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के लिए तैयार होगा. साथ ही यह भी सवाल है कि क्या सऊदी सरकार एफ-35 के ठिकानों के आसपास मौजूद चीनी कंपनियों हुआवेई और जेडटीई के संयंत्रों को हटाने या उनकी पहुंच सीमित करने को तैयार होगी. अमेरिकी विदेश विभाग पहले भी संवेदनशील संचार ढांचे में भरोसेमंद तकनीकी आपूर्तिकर्ताओं के इस्तेमाल पर जोर देता रहा है.

## एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस

**नई दिल्ली।** विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको एस जयशंकर को एसआईआर के तहत चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है. इस लिस्ट में सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद और उनका परिवार, पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी समेत सुप्रीम कोर्ट की पूर्व रंजना देसाई और उनके परिवार को भी आयोग ने नोटिस दिया है. चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस में कई मौजूदा और रिटायर्ड सीनियर अधिकारी शामिल हैं. उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी. चुनाव आयोग उनकी मौजूदा जानकारी को पिछली बार हुए रिविजन के दौरान बनी वोटर लिस्ट की जानकारी से नहीं जोड़ पाया है. इधर, नोटिस को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच दिल्ली के मुख्य चुनाव आधिकारी ने साफ कह दिया है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि पाने वालों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे. ऊपर बताई गई कैटेगरी के लोगों ECINET में अपना डेटा ठीक करने के लिए सिस्टम से बने नोटिस भेजे जा रहे हैं. बिना अपनी बात रखने का मौका दिए और बिना सही, ठोस, और अपील करने लायक आदेश खे किसी खा नाम नहीं हटाया जा सकता है।

## एशियन गेम्स में 22 सितंबर को होगा भारतीय पुरुष टीम का पहला मैच

**नई दिल्ली।** 2026 एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 119 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया. महिला टीम को अब गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ना है, जो 22 सितंबर को खेला जाएगा. मगर मेंस टीम के अभी दूर-दूर तक कोई दर्शन नहीं हुए हैं. भारत की मेंस टीम जापान के लिए रवाना हो गई है, जहां उसे 22 सितंबर को जापान के साथ मुकाबला खेलना है. यह मैच एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं होगा. 22 सितंबर को यह मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है. आखिर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच कब और किसके साथ खेलेगी? भारतीय मेंस टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी. उसका प्रतिद्वंदी कौन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. दरअसल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा बाकी 6 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में जो भी टीम दूसरे स्थान पर फिनिश करेगी, उसका सामना 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में भारत के साथ होगा. दूसरे ग्रुप में हॉन्ग-कॉन्ग, मलेशिया और ओमान को रखा गया है.

## इस हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद

**नई दिल्ली।** 21 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में बैंक जाकर अपना कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. दरअसल, इस दौरान रीजनल छुट्टियों और वीकेंड के चलते बैंक के कामकाज पर असर पड़ेगा. 21 सितंबर से 27 सितंबर, 2026 के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 6 दिन बंद रहेंगे. 21 सितंबर 2026 (सोमवार)- गुवाहाटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में श्रीमंत शंकरदेव की जयंती और श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. 22 सितंबर 2026 (मंगलवार)- कर्मा पूजा के मौके पर रांची में बैंकों की छुट्टी रहेगी. 23 सितंबर 2026 (बुधवार)- महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा. 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)- इंद्रजात्रा के पावन त्योहार पर गंगटोक (सिक्किम) में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 26 सितंबर 2026 (शनिवार)- महीने का चौथा शनिवार होने के कारण पूरे भारत में सभी बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. 27 सितंबर 2026 (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से देशभर के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

## NTPC ने कैंसिल किया 400 करोड़ का टेंडर

**नई दिल्ली।** देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी (NTPC) ने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने शनिवार को कहा कि उसने GR Infraprojects के 400 करोड़ रुपये के टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जो महाराष्ट्र के मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर 400-MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और प्रोजेक्ट में जरूरी प्रोग्रेस हासिल करने में नाकाम रहा।

# UPI नहीं तो कार्ड पर 2% चार्ज लगा सकता है दुकानदार?

**नई दिल्ली।** यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर बवाल जारी है. व्यापारी वर्ग इसका खूब विरोध कर रहे हैं. व्यापारियों ने साफ कहा है कि हम 15 अक्टूबर के बाद 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. इस बीच अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अगर यूपीआई से पेमेंट नहीं होगा तो लोग या तो कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को लेकर पहले ही व्यापारी ग्राहकों से 2% के हिसाब से चार्ज वसूलते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या 2% चार्ज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कोई नियम बनाया है. जानिए आरबीआई का इसपर क्या कहना है.

### RBI ने क्या बताया?

RBI ने स्पष्ट किया है कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर ऐसे चार्ज को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो उसका भुगतान न करें और साथ ही दुकानदार एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए ले रहा है, इस बारे में जरूर पूछे.

### शिकायत कर सकते हैं आप

अगर दुकानदार आपके पीछे पड़ता है और बार-बार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए कहता है तो ऐसे में आप सीधा शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप संबंधित बैंक या फिर कार्ड जारी करने वाली संस्थान से भी शिकायत कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो आप सीधे RBI के शिकायत पोर्टल की मदद से भी मामला दर्ज करवा सकते हैं. इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कि अगर कोई दुकानदार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो आप बिल्कुल भी पैसे न दें.

### कैसे करें शिकायत?

सबसे पहले तो आप संबंधित बैंक के पास शिकायत करें और अगर आपकी समस्या का वहां पर कोई समाधान नहीं होता है तो आप सीधे RBI के CMS( Complaint Management System) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं.

- शिकायत करने के लिए सबसे पहले आप RBI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर जाएं.
- इसके बाद आपको यहां पर File a Complaint का ऑप्शन मिलेगा.
- फिर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, उन सभी जानकारियों को भरें.
- अब आपको संबंधित बैंक का नाम चुनना होगा.
- इसके बाद शिकायत की कैटेगरी में Violation of Rules/ Merchant Practices का ऑप्शन चुनें.
- फिर दुकानदार का नाम क्या है और एड्रेस भरकर शिकायत सबमिट कर दें.

## 'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम

**नई दिल्ली।** वसीम अकरम ने बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट के बाद ही कप्तानी से हट जाना चाहिए था. उन्होंने उस बयान का भी मजाक बनाया, जो बाबर ने तीसरे टेस्ट से पहले दिया था. बता दें कि इतिहास में पहली बार हुआ जब इंग्लैंड में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ हुआ, तीनों मैचों में इंग्लैंड आसानी से जीत गई.बाबर आजम ने तीसरे टेस्ट से पहले कहा था कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद टीम में हुए बदलावों की जानकारी उन्हें भी नहीं थी. दरअसल पीसीबी ने 7 खिलाड़ियों को स्क्वॉड से बाहर कर घर भेज दिया था, इसने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया था. कई खिलाड़ियों के फोन जब्द कर लिए गए थे. यहां तक कि हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया था. मैनचेस्टर में एक कार्यक्रम में वकार यूनिस के साथ बातचीत में वसीम अकरम ने बाबार आजम के बयान पर मजाक बनाते हुए कहा कि अगर उन्हें टीम में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी नहीं थी तो आप वहां क्या कर रहे थे? आप क्या चने बेचने के लिए गए थे? अकरम ने बाबर की कप्तानी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को लगना चाहिए कि आपका कप्तान आपके लिए खड़ा रहेगा।

# चंद्रशेखरन की ताजपोशी को Tata Trust ने बताया गैर-कानूनी

**नई दिल्ली।** टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस बोर्ड की ओर से एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने को गैर कानूनी बताया है और बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया है. टाटा ट्रस्ट्स का साफ कहना है कि बोर्ड की बैठक में पड़े 4:1 के वोट का कोई कानूनी मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के नियमों के तहत चेयरमैन की नियुक्ति के लिए ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स की सहमति अनिवार्य शर्त है, जो कि पूरी नहीं हुई.

टाटा संस के बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए दोबारा चैयरमेन के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स ने इस फैसले को कानूनी रूप से शून्य करार दिया है. टाटा ट्रस्ट्स ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि कंपनी के नियमों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों का सकारात्मक समर्थन किसी भी निर्णय लेने के लिए बोर्ड को नहीं दिया गया था.

ट्रस्ट्स ने बोर्ड की ओर से 'कास्टिंग वोट' के इस्तेमाल के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि जब नियम साफ हैं तो इसे गतिरोध नहीं कहा जा सकता. टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि अध्यक्ष का निर्णायक मत केवल तभी लागू होता है, जब पूरे बोर्ड में मतों की बराबरी हो. यह टाटा ट्रस्ट्स के मनोनीत निदेशकों पर लागू नहीं होता. चाहे मतदान का रिजल्ट 4:1 रहा हो या कोई और आंकड़ा, यह मान्य योग्य नहीं है.

# ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत

**नई दिल्ली।** ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे जीत की दहलीज पर खड़ी थी, एक के बाद एक गिरते विकेट से मेजबान की उम्मीद जग गई थी लेकिन अंत में मेहमान टीम ने बाजी मार ली और 1 विकेट से मैच जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस मैच के हीरो जोश इंग्लिस रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा. अंत में नेथन एलिस ने 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

272 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब हुई थी. कप्तान मिचेल मार्श 8 और ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट हो गए थे. दोनों ओपनर्स को ब्रैड इवांस ने आउट किया. इसके बाद जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी (52) हुई, ग्रीम कीमर ने कोनोली (21) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा. इंग्लिस ने चौथे विकेट के लिए एलेक्स कैरी के साथ 85 रनों की साझेदारी की, इसमें कैरी के सिर्फ 34 रन थे. इस साझेदारी को भी ब्रैड इवांस ने तोड़ा था, उन्होंने कैरी को कैच आउट कराया।

## पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?

**नई दिल्ली।** सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के दावे वायरल होते हैं, जिस पर कई लोग तो आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं. लेकिन असल में उसके पीछे की सच्चाई जाननी जरूरी होती है. ऐसे में इन दिनों भी सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप से जुड़ा एक मैसेज जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहां जा रहा है कि अब पेट्रोल पंपों पर 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर रोक लगाई जाएगी. इतना ही नहीं, बल्कि 23 सितंबर को नौ UPI डे मनाने की भी बात सामने आई है. लेकिन हकीकत में इस दावे की सच्चाई क्या है ये जानना सभी के लिए काफी जरूरी है. इस दावे की सच्चाई क्या है उस बारे में भी जानकारी दी है. दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर 2000 से ज्यादा का भुगतान UPI से करता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा. यानी मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप मालिक 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर MDR लागू किए जाने का विरोध करेंगे. साथ ही 23 सितंबर 2026 को इंदौर में नौ UPI डे मनाने तक की बात कही गई है. इंडियन ऑयल ने एक्स पर इस दावे की सच्चाई बताई है. एक्स पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. उन्होंने 2000 से ज्यादा के यूपीआई पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है।

# अगले महीने से महंगी होंगी रोजमर्रा की वस्तुएं

**नई दिल्ली।** अगर आप अक्टूबर से त्योहारों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपकी जेब का बजट बिगाड़ सकती है. देश की कई बड़ी कंज्यूमर कंपनियां लगातार दूसरे 3 महीने में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें ज्यादा करने जा रही हैं. डिटर्जेंट, साबुन, बर्तन धोने की बार, नमक, पेंट, टायर और कई दूसरे रोजमर्रा के सामान महंगे होने वाले हैं. कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल और फ्यूल महंगा होने की वजह से दाम ज्यादा करना मजबूरी हो गया है.

देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि आने वाले 3 महीने में डिटर्जेंट और बर्तन धोने की बार जैसी होम केयर कैटेगरी में एक एक कर के कीमतें ज्यादा की जाएंगी. इसके अलावा एशियन पेंट्स, डोडला डेयरी समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी प्राइस हाइक का हिंट दिया है. कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल से बनने वाले कच्चे माल की कीमतें लगातार ज्यादा हो रही हैं, जिससे कॉस्ट पर दबाव ज्यादा हो गया है.

### मिडिल ईस्ट तनाव का असर

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान से जुड़े हालात का असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा रहने से कंपनियों को प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है. इसी वजह से हैवेल्स इंडिया अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 8% तक ज्यादा कर दी है, जबकि टाटा कंज्यूमर ने नमक की कीमत करीब 7% ज्यादा कर दी है. अगर यही हाल बनी रही तो आने वाले महीनों में और भी कंपनियां कीमतें ज्यादा कर सकती हैं.

अक्टूबर से दिसंबर तक देश में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं. यही समय कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिक्री वाला सीजन होता है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मजबूत मांग के लिए कस्टमर ज्यादा हुई कीमतों के बावजूद खरीदारी करेंगे और इसका असर बिक्री पर ज्यादा नहीं पड़ेगा.

### वीजा से पहले 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा

# US के नए वीजा नियम ने बढ़ाई चिंता

**वाशिंगटन** अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को स्थायी बना दिया है. इसके तहत कॉन्सुलर अधिकारी बिज़नेस और टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करने वाले कुछ विदेशी नागरिकों से वीजा जारी करने से पहले 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकते हैं. इस फैसले की घोषणा शुक्रवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित एक नोटिस के जरिए की गई. यह नियम 50 देशों के B-1 और B-2 वीजा आवेदकों पर लागू होगा, जिनमें से अधिकतर देश अफ्रीका में हैं. यह नया नियम 3 अगस्त से लागू हो जाएगा.

नोटिस के अनुसार, कॉन्सुलर अधिकारी वीजा जारी करने की शर्त के रूप में संबंधित गैर-प्रवासी वीजा आवेदकों से अपनी तरफ से तय की गई राशि का बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकते हैं. यह राशि अधिकतम 20,000 डॉलर तक हो सकती है. वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को पहली बार वर्ष 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. इसका मकसद यह जांचना था कि क्या आर्थिक बॉन्ड की व्यवस्था वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुकने वाले लोगों की संख्या कम करने में मदद कर सकती है.

अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस पायलट प्रोग्राम से मिले नतीजे इतने पॉजिटिव रहे कि इसे स्थायी रूप से लागू करने का फैसला लिया गया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में कहा गया है कि 2025 के वीजा बॉन्ड पायलट प्रॉग्राम ने विदेश विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और ट्रेजरी विभाग को इस योजना की व्यवहारिकता का आकलन करने का मौका दिया और इससे यह साबित हुआ कि बॉन्ड प्रोग्राम वीजा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है. भारत इस सूची में शामिल नहीं है. वर्तमान में भारत के नागरिकों को B-1 या B-2 वीजा के लिए आवेदन करते समय इस नए नियम के तहत कोई वीजा बॉन्ड जमा नहीं करना होगा.

अमेरिका के विदेश विभाग ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया जा सकता है और इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है. यह कार्यक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से लागू किए गए बड़े इमिग्रेशन अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. जब यह योजना पायलट आधार पर शुरू की गई थी, तब कॉन्सुलर अधिकारी आवेदकों से 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर या 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड मांग सकते थे. अब स्थायी नियम में 5,000 डॉलर वाला विकल्प हटा दिया गया है और अधिकतम राशि बढ़ाकर 20,000 डॉलर कर दी गई है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस नीति का मुख्य मकसद लोगों को अपने वीजा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में अवैध रूप से रुकने से रोकना है. हालांकि, इमिग्रेशन समर्थकों का मानना है कि इससे वास्तविक कारोबारी यात्रियों और घूमने-फिरने के लिए आने वाले पर्यटकों पर भी असर पड़ सकता है और वे अमेरिका आने से हतोत्साहित हो सकते हैं. ट्रंप प्रशासन ने हाल के समय में इमिग्रेशन नियमों को और सख्त किया है. कुछ वीजा श्रेणियों के लिए फीस बढ़ाई गई है और वीजा आवेदकों तथा अमेरिका में पहले से रह रहे कुछ प्रवासियों की सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच भी बढ़ा दी गई है.

## 6 साल बाद भारत-चीन व्यापार शुरू

**नई दिल्ली।** भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार करीब छह साल बाद फिर शुरू हो गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान बंद हुए इस पारंपरिक व्यापार मार्ग को अब दोबारा खोला गया है. लिपुलेख पास (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला (सिक्किम) जैसे प्रमुख रास्तों से व्यापार गतिविधियां दोबारा शुरू होने जा रही हैं. इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों के व्यापारियों, स्थानीय कारोबार और छोटे उद्योगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. लंबे समय से बंद पड़े इस व्यापार से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

### भारत से चीन को क्या-क्या भेजा जाएगा?

ऊन और ऊनी उत्पाद, पश्मीना उत्पाद, कालीन और हस्तशिल्प सामान, कृषि उत्पाद, जड़ी-बूटियां और हर्बल उत्पाद, स्थानीय स्तर पर तैयार वस्तुएं, लंदन जाने वाली डायरेक्ट उड़ानें बंद, देश की इस बड़ी विमान कंपनी ने लिया फैसला

### चीन से कौन-कौन सी चीजें आ सकती हैं?

ऊनी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रोजमर्रा के उपयोग की चीजें, मशीनरी और छोटे उपकरण, कुछ कृषि और घरेलू उपयोग की चीजें।

## सेवा संकल्प से साकार हुआ पक्के आशियाने का सपना,

**शहर सत्ता/रायपुर।** सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सेवा की नई कहानी लिख रही हैं। रामानुजनगर जिला सूरजपुर निवासी श्रीमती मधु जायसवाल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिला पक्का घर वर्षों के इंतजार के बाद साकार हुआ सपना है। नए आशियाने में भगवान गणेश की स्थापना के साथ परिवार की खुशियों को नया अर्थ मिला है। कभी कच्चे मकान में रहने वाले श्रीमती मधु जायसवाल के परिवार के लिए बारिश का मौसम चिंता लेकर आता था। टपकती छत, घर में भरता पानी और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने की चुनौती के बीच परिवार हर मौसम कठिनाइयों से गुजरता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना वर्षों तक उनके लिए एक अधूरा सपना बना रहा।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद परिवार के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। शासन से मिली सहायता से उनका पक्का घर तैयार हुआ और परिवार को कच्चे मकान की परेशानियों से स्थायी राहत मिली। अब परिवार अपने सुरक्षित और सुविधाजनक आशियाने में सुकून के साथ जीवन बिता रहा है।

## आयुष्मान कार्ड ने थामा अमृत का हाथ, इलाज की चिंता हुई दूर

**शहर सत्ता/रायपुर।** सेवा का अर्थ केवल सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में किसी जरूरतमंद के साथ मजबूती से खड़े होना है। सेवा संकल्प अभियान इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम जवाहरनगर निवासी 32 वर्षीय श्री अमृत कुमार मण्डल के जीवन में आयुष्मान कार्ड ने इसी सेवा संकल्प को साकार किया। गंभीर दुर्घटना में कलाई की कई हड्डियां टूटने के बाद जब महंगे इलाज की चिंता सामने थी, तब आयुष्मान कार्ड उनके परिवार के लिए उम्मीद और भरोसे का सहारा बन गया। लघु कृषक परिवार के श्री अमृत कुमार अगस्त 2026 में घर के आंगन में चलते समय अचानक फिसलकर गिर गए। हादसे में उनकी कलाई में गंभीर चोट आई। प्रारंभिक उपचार के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि उनकी परेशानी बढ़ती गई। इसके बाद रामानुजगंज के संजीवनी हॉस्पिटल में जांच कराई गई, जहां कलाई की कई हड्डियां टूटने की पुष्टि हुई और तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई। इसी कठिन समय में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना उनके लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिला और अस्पताल में उनका सफल ऑपरेशन किया गया।

## मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनी राजेन्द्र प्रसाद का सहारा

**शहर सत्ता/रायपुर।** सेवा संकल्प अभियान की भावना तब सार्थक होती है, जब जरूरत के समय शासन की संवेदनशील पहल किसी व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद बनकर पहुंचे। बलरामपुर जिला के ग्राम पस्ता निवासी 63 वर्षीय श्री राजेन्द्र प्रसाद की कहानी इसका उदाहरण है। छोटी जोत के किसान श्री राजेन्द्र प्रसाद को फरवरी 2026 में तेज कमर दर्द की शिकायत हुई। अम्बिकापुर में उपचार के बाद भी राहत नहीं मिलने पर परिजन उन्हें रायपुर के बालको हॉस्पिटल ले गए। जांच में मल्टीपल मायलोमा नामक कैंसर की पुष्टि हुई। लगभग 15 लाख रुपये के उपचार का खर्च सुनकर परिवार के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे समय में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनके लिए सहारा बनी। योजना के अंतर्गत सहायता मिलने से बालको हॉस्पिटल में उनका उपचार शुरू हुआ और लगभग 15 लाख रुपये का पूरा उपचार निःशुल्क हुआ।

# भविष्य के उद्योगों का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

## मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में किया 'इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026' का शुभारंभ





**शहर सत्ता/रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और यहां उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी पारंपरिक औद्योगिक ताकत के साथ नई अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खनिज, ऊर्जा, वन संपदा, पर्याप्त मानव संसाधन और देश के मध्य में अनुकूल भौगोलिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ताकत है। राज्य सरकार इन खूबियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर अधोसंरचना और निवेशक हितैषी नीतियों से जोड़कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भूमिका केवल उद्योगों के लिए नियामक की नहीं है। हम सरकार को उद्योग और निवेश की राह आसान करने वाले सहयोगी और 'एक्सीलरेटर' के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निवेश का प्रस्ताव आने से लेकर उद्योग के धरातल पर स्थापित होने तक हर चरण में निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक आयोजन के लिए रायपुर का चयन किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विस्तार होने से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती देशभर के 750 से अधिक जिलों में उद्यमियों को संगठित कर उद्योग और उद्यमिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में भी 1200 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन से जुड़े हैं। 18 से 20 सितम्बर तक आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देशभर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों की भागीदारी इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक मेला केवल उत्पादों और तकनीकों की प्रदर्शनी नहीं है। यह उद्यमियों के बीच संवाद, अनुभव, नवाचार और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नई संभावनाओं पर चर्चा होगी और युवाओं को उद्योग तथा उद्यमिता की दुनिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

## लघु उद्योगों और एमएसएमई को मजबूत बना रही सरकार

**शहर सत्ता/रायपुर।** वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्योग, रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देश का लक्ष्य और ध्येय है। इसी विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ भी देश के अग्रणी राज्यों के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार दीर्घकालिक रोडमैप के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ कार्य प्रारंभ किया है। विकास के साथ देश की विरासत और सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और आने वाले वर्षों में देश के विकास की गति को और तेज करने के लिए संरचनात्मक सुधारों तथा दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजना विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 'अंज़ोर विजन डॉक्यूमेंट' तैयार कराया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

# पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर ने ली वर्चुअल साप्ताहिक समीक्षा बैठक





**रायपुर।** पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने वर्चुअल साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीएसपीडीसीएल के अधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉ. सिंह ने बिजली विभाग को निर्देशित किया कि सभी शासकीय कार्यक्रमों में वह एक स्टॉल लगाकर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं । बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत नहीं किया जाए। यदि किसी कारणवश आवेदन निरस्त किया जाता है, तो संबंधित आवेदक को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से बताया जाए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत आम नागरिकों को लाभ प्राप्त करने एवं ऋण लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन ने बैंक, सीएसपीडीसीएल और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर देते हुए योजना की स्वीकृति, ऋण वितरण एवं सोलर इंस्टॉलेशन की साप्ताहिक समीक्षा निरंतर जारी रखने की बात कही। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

## लंबित राजस्व प्रकरणों एवं भारत माला परियोजना भू-अर्जन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर संभागायुक्त श्याम धावडे की अध्यक्षता में 19 सितम्बर 2026 को प्रातः 11 बजे कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग के सभाकक्ष में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं भारतमाला परियोजना से संबंधित भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर संभाग अंतर्गत संबंधित जिलों के अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन से संबंधित अधिकारी तथा भारतमाला परियोजना के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान नामांतरण, खाता विभाजन, व्यपवर्तन एवं सीमांकन से संबंधित लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली गई। बैठक में भारतमाला परियोजना से संबंधित भू-अर्जन प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। भू-अर्जन प्रकरणों में मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों से संबंधित मूल अभिलेख एवं जवाबदावा की स्थिति की जानकारी ली गई।

# प्रोजेक्ट ग्रीन पालना: प्रसूता माताओं को हरियाली की भेंट

## पर्यावरण संरक्षण का संदेश

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा "प्रोजेक्ट ग्रीन पालना" अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभिनव पहल के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के उपरांत प्रसूता माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि एक नई जिंदगी के आगमन के साथ धरती पर एक नए वृक्ष का भी जन्म हो। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 19 सितंबर 2026 को इस अभियान के तहत 14 प्रसूता माताओं को कुल 70 फलदार पौधे भेंट किए गए।

जिसमें

एम सी एच कालीबाड़ी 03, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य -बिरगांव - 02, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोवा- 01, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर - 06, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा - 02। इस परियोजना के प्रारंभ से अब तक जिले में कुल 13,514 माताओं को 67,570 पौधे भेंट किए जा चुके हैं।यह प्रयास मातृत्व के उत्सव को प्रकृति से जोड़ने का एक सार्थक कदम है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न केवल नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखता है।र प्रसव के बाद 5 पौधे - आम, अमरूद, आंवला, पपीता, मुनगा। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिस्चार्ज के समय प्रसुताओं को अपनी गोद में बच्चे के साथ 5 फलदार पौधे दे रहे हैं।

**इन 5 पौधों से क्या-क्या फायदे हो रहे हैं:**

1. आम - आने वाले सालों में छाया और आमदनी का स्रोत। परिवार का आर्थिक सहारा।
2. अमरूद - विटामिन-C से भरपूर, बच्चों और माँ के लिए प्राकृतिक पोषण।
3. आंवला - आयुर्वेद का खजाना, इम्यूनिटी बूस्टर। माता के स्वास्थ्य के लिए वरदान।
4. पपीता - जल्दी फल देने वाला, पाचन के लिए अच्छा, साल भर पोषण।
5. मुनगा (सहजन) - इसे सुपरफूड कहा जाता है। इसके पत्तों में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम और आयरन। प्रसूता माता के लिए अमृत समान।

**घर और परिवार में क्या बदलाव आया?**

पहले: घर का आँगन खाली, पोषण के लिए बाजार पर निर्भरता।

अब: आँगन में हरियाली, घर का वातावरण ठंडा और शुद्ध। महिला रोज पौधे में पानी देती है तो उसका मन प्रसन्न रहता है, पोस्ट-डिलीवरी तनाव कम होता है। एक लाभार्थी माँ ने कहा - "पहले लगता था बच्चा पालना मुश्किल है। अब लगता है जैसे मेरे बच्चे के साथ 5 और बच्चे भी मेरे आँगन में पल रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा रोज कहता है - माँ, मेरे पेड़ में पानी डाला क्या?"यही सोच हर घर हरियाली की दिशा में ले जा रही है।

# ड्रोन सर्वे बना वरदान, आमदी के घनश्याम को मिला पुश्तैनी जमीन का पट्टा



**रायपुर।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों के सपनों को साकार कर रही है। रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के ग्राम आमदी के निवासी श्री घनश्याम सिन्हा के जीवन में इस योजना ने बड़ा बदलाव लाया है। घनश्याम सिन्हा पिता श्री जगदीश सिन्हा अपने परिवार के साथ ग्राम आमदी में पीढ़ियों से अपने पैतृक घर में निवास कर रहे हैं। मकान और जमीन पर कब्जा तो उनका था, लेकिन उनके पास इसका कोई औपचारिक कानूनी दस्तावेज नहीं था। खसरा नंबर 676/21 की आबादी भूमि का पट्टा न होने से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए कोई आधिकारिक अभिलेख नहीं था, सीमा विवाद की आशंका बनी रहती थी और बैंक ऋण लेने में कठिनाई होती थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी अड़चन आती थी।

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्राम आमदी में आबादी भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण और सटीक सीमांकन कराया गया। इसके बाद विधिवत प्रक्रिया पूरी कर श्री घनश्याम सिन्हा जी को उनके आवासीय भूखंड का अधिकृत आबादी पट्टा (प्रॉपर्टी कार्ड) सौंपा गया। पट्टा मिलने से उन्हें स्पष्ट एवं निर्विवाद मालिकाना हक मिला है, जिससे उनके स्वामित्व को कानूनी सुरक्षा मिल गई है। अब वे प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर मकान के नवीनीकरण एवं विस्तार के लिए बैंकों से आसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई बाधा नहीं रहेगी। ड्रोन आधारित सटीक मैपिंग से सीमा रेखाएं स्पष्ट होने से भूमि विवादों से भी मुक्ति मिल गई है। पट्टा प्राप्त होने पर खुशी जाहिर करते हुए श्री घनश्याम सिन्हा ने कहा कि हम वर्षों से इसी घर में रह रहे थे, लेकिन अपना कहने के लिए कोई पक्का कागज नहीं था। स्वामित्व योजना के तहत पट्टा मिलने से हमारे सिर की छत को स्थायी सुरक्षा और पहचान मिल गई है। अब हमें सरकारी योजनाओं और वित्तीय सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा।

# दो साल से 'अनुशासन' गया था तेल लेने

## दो साल बाद अनुशासन समिति को आया बैठक का ख्याल

**बहुतेरी शिकायतों के बावजूद प्रकरण समिति को नहीं भेजा**

**कांग्रेस में 36 नेताओं की वापसी पर अब भी मंथन**

**अमित-रेणु जोगी, बृहस्पति सिंह पर फैसला नहीं**

**नए प्रभारी सुखदेव भगत 29 सितंबर को लेंगे बैठक**

छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सूरमाओं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन पसंद नेताओं को दो साल बाद अनुशासन समिति की सुध आई है। खुद फील गुड़ कर रहे प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान समिति सदस्य यूं आनन-फानन में बैठक जो किये उसकी कुछ और ही। खुद को अनुशासित बताने की नाकाम कोशिश करते अनुशासन समिति सदस्यों ने अब तक बहुतेरी शिकायतों के बावजूद प्रकरण समिति को नहीं भेजा था। अब पार्टी हलकों में चर्चा है कि आनन-फानन में बैठक 11 नए प्रभारी की समीक्षा के पहले गतिविधियां दिखाने की कोशिश मात्र है।

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी के दौरे से पहले पीसीसी को अनुशासन समिति की याद आई। लगभग दो साल पहले गठित कांग्रेस की अनुशासन समिति अब तक सिर्फ कागजों में ही सिमटकर रह गई थी। नए प्रभारी सुखदेव भगत पहले दौरे में अनुशासन समिति की भी बैठक लेंगे। इन सूचनाओं के बाद पीसीसी ने आनन-फानन में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई। करीब दो साल बाद राजीव भवन में हुई पहली बैठक में जैसे-तैसे कुछ फैसले भी लिए गए। ताकि प्रभारी की मौजूदगी में समीक्षा के दौरान समिति के कार्यों का ब्यौरा पेश किया जा सके।

राजीव भवन में कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी से निष्कासित नेताओं की वापसी के 36 आवेदनों पर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में हुई बैठक में विधानसभा और निकाय चुनाव के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई। कुछ मामलों में निष्कासन समाप्त करने का फैसला लिया गया, जबकि कई प्रकरणों को फिलहाल लंबित रखा गया। इस बैठक में अमित जोगी, रेणु जोगी और बृहस्पति सिंह से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। अमित जोगी के मामले में समिति ने फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया और प्रकरण लंबित रखा है।

इस बैठक में पार्टी अनुशासन को लेकर भी चर्चा हुई। समिति ने स्पष्ट किया कि, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी या गतिविधियों को अनुशासनहीनता के तौर पर देखा जा सकता है। मीडिया के जरिए दिए गए पार्टी विरोधी बयान भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इस समिति ने विधानसभा और निकाय चुनाव के दौरान नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामलों पर भी विचार किया। इसके साथ ही कांग्रेस में दोबारा प्रवेश के लिए मिले आवेदनों पर भी चर्चा हुई।

### अनुशासनहीनता के कई मामले पेंडिंग, सिर्फ औपचारिकता

इसी बीच लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अनुशासनहीनता के कई मामले आए लेकिन समिति में कोई मामला नहीं भेजे जाने से विचार तक नहीं हो पाया। पार्टी से बगावत कर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागियों को चुनाव के बाद बाकायदा पार्टी में वापस भी ले लिया गया। अब नए प्रभारी सुखदेव भगत 29 सितंबर को राजीव भवन में अनुशासन समिति की बैठक लेंगे। इससे पहले समिति की बैठक बुलाकर प्रकरणों को सूचीबद्ध करने की औपचारिकता पूरी कर ली गई।

### पायलट के निर्देश पर हुआ था अनुशासन समिति का गठन

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महासचिव सचिन पायलट के निर्देश पर अनुशासन समिति का गठन हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू को चेयरमैन बनाकर समिति की कमान सौंपी गई थी। इन दो वर्षों में गठन के बाद समिति की एक औपचारिक बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद अनुशासन समिति कागजों में ही सिमटी रही। इस दौरान बड़े नेताओं को लेकर भी अनुशासनात्मक मामले लगातार सामने भी आए लेकिन बयानबाजी और नोटिस के बाद संगठन ने प्रकरणों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यहां तक कि समिति को एक भी प्रकरण नहीं भेजे गए। इसे लेकर कई मौकों पर शिकायतें भी हुईं।

# छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल

## टीएस सिंहदेव का बयान और 52 करोड़ की घटती संपत्ति

छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक वीडियो और उनकी घटती संपत्ति ने बड़ा भूचाल ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस के इकलौते 'महाराजा' की आर्थिक स्थिति और उनके इस खुलासे ने कि उन्हें घर का बजट और सियासी खर्च चलाने के लिए अपनी संपत्तियों यानी 'तपस्या' को बेचना पड़ रहा है, राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक जोरदार चर्चा छेड़ दी है।

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक अनौपचारिक वीडियो और उनकी घटती संपत्ति राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है। वीडियो में सिंहदेव द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उन्हें घर का बजट और सियासी खर्च चलाने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्तियों यानी 'तपस्या' को बेचना पड़ रहा है, राजनीतिक गलियारों में जोरदार हलचल मच गई है।

### 5 साल की सत्ता और 52 करोड़ की गिरावट

सामान्य तौर पर राजनेताओं की संपत्तियों में सियासत में आने के बाद भारी उछाल देखने को मिलता है, लेकिन टीएस सिंहदेव का मामला इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। साल 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तब चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार टीएस सिंहदेव के पास 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी।

इसके बाद भूपेश बघेल सरकार में वे उपमुख्यमंत्री और मंत्री रहे, लेकिन इन पांच सालों के भीतर उनकी संपत्ति का ग्राफ नीचे आया। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति घटकर 450 करोड़ रुपये से भी कम (लगभग 447 करोड़) दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि अचल संपत्तियों के दाम बढ़ने के बावजूद सिंहदेव की संपत्ति में आई 52 करोड़ रुपये से ज्यादा की यह भारी कमी जमीनों की लगातार बिक्री की वजह से हुई है।

### अनौपचारिक बातचीत का वीडियो और सियासी मायने

विस्तार न्यूज चैनल सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चली खबरों के मुताबिक, सिंहदेव का यह वीडियो एक हल्के-फुल्के और अनौपचारिक अंदाज में सामने आया है। हालांकि, बातचीत भले ही सहज और हास्यपूर्ण लग रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और दोनों नेताओं के बीच की अंदरूनी खींचतान किसी से छिपी नहीं रही है। ऐसे माहौल में सिंहदेव का यह कहना कि उन्हें घर का बजट और राजनीतिक खर्च चलाने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्तियों (तपस्या) को बेचना पड़ रहा है, उनके राजनीतिक संघर्ष और वर्तमान स्थिति को लेकर नई चर्चाओं को हवा दे गया है।

### भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और सिंहदेव पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी कलह और घुटन अब नेताओं के बयानों के जरिए बाहर आने लगी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी ही पार्टी के दिग्गज और समर्पित नेताओं के योगदान का मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसके कारण आज प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता को अपनी पैतृक संपत्तियों और 'तपस्या' को दांव पर लगाने की बात सार्वजनिक तौर पर कहनी पड़ रही है। बहरहाल, चुनाव के बाद भी सिंहदेव की संपत्ति और उनका यह बयान छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिज़ा में लगातार गर्माहट बनाए हुए है।

### घर, पार्टी और राजशाही की चर्चा

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जितने शालीन हैं, उतने ही संसाधन संपन्न भी माने जाते हैं। सरगुजा में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 'तपस्या आउ की कोठी आउ लौटकर' के जवाब में सरगुजा महाराज का जो बयान सामने आया, उसने पार्टी से लेकर मीडिया तक को चौंका दिया। बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने संपत्ति बेचने का खुलासा किया और इसकी वजह भी बताई। इस खुलासे के साथ ही इस बात का भी राजफाश हुआ कि वे आमतौर पर अपनी सियासत का खर्च पार्टी फंड से नहीं, बल्कि अपने घर के पैसों से चलाते हैं। चर्चा है कि 'तपस्या' का सौदा तकरीबन 44 करोड़ रुपये में हो सकता है। राजनीतिक पंडित इसका यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि महाराज साहब इन्हीं पैसों से घर का खर्च भी चलाएंगे और भविष्य की राजनीति में भी इनका उपयोग करेंगे।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27